

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी— श्री इन्द्र सिंह राव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 60/2018

बउनवान

दौलतराम पुत्र देवीलाल जाति—बैरवा, निवासी—बालून्दा
तहसील—मोंगरोल जिला—बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार, मोंगरोल

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—1. श्री बृजमोहन गोयल, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)
(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक — 16.01.2019



1— अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मोंगरोल के आदेश दिनांक 16.02.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—बालून्दा, तहसील—मोंगरोल की आराजी ख०न० 147 रकबा 0.16 है० किस्म गै.मु नहर पर अतिकमी मानकर बेदखली, 256/-रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में निर्णय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का सही तथ्य सत्यापन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अतिचारी बाबत सत्यापन नहीं किया है। अनुपस्थिति में निर्णय फरमाया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिला है। अपीलांट का किस्म गै.मु नहर पर कब्जा नहीं है और ना ही उक्त प्रकरण में उसे विधिवत तहसीलदार द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.02.2018 निरस्त फरमाया जावे।

2— इस प्रकरण में अपील रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अपील में अपील का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर निर्णय परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3— बहस के दौरान अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अधिकार नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपील में उक्त आराजी पडत पडी हुई राशि जमा करा दी है।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। साथ ही कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.02.2018 निरस्त फरमाया जावे।

4- इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 25/17 निर्णय दिनांक 08.02.2017 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5- हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी किया गया है, नोटिस की प्रोपर तामील हुयी है, इसके बावजूद अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। विवादित आराजी गै.मु.नहर है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 25/17 निर्णय दिनांक 08.02.2017 से बेदखल किया गया है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप ही सजायाबाद न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जा सकता।

6- परिणामस्वरूप, अपीलांट को उक्त निर्णय खण्डन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रागेश्वर द्वारा प्रकरण संख्या 83/18 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2018 को रथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2018 को जजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



सत्यमेव जयते (इन्द्र सिंह राव)

Web Copy - Not Official